International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

# भारतीय अर्थ पर वसीयतनामा उत्तराधिकार में पारिवारिक कानून का एक अध्ययन

**VISHWA MOHAN MISHRA**
**RESEARCH SCHOLAR DEPARTMENT OF LAW OPJS UNIVERSITY, CHURU, RAJASTHAN**

**DR. RAVI TYAGI**
**PROFESSOR DEPARTMENT OF LAW OPJS UNIVERSITY, CHURU, RAJASTHAN**

**सारांश**

1865 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पहले भारत में नियंत्रित था। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंग्रेजी कानूनों पर आधारित था और कुछ अपवादों के अधीन, सभी प्रकार की वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार के लिए प्रभावी नियम था। हालाँकि, अपवाद इतने व्यापक थे कि सभी भारतीयों को छूट थी। हिंदू वसीयत अधिनियम भी 1870 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की कुछ धाराएं सभी हिंदुओं की वसीयतों और संहिताओं तक फैली हुई हैं। 1881 में इस अधिनियम को अपनाया गया और इस अधिनियम को हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों पर भी लागू किया गया। अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पहले के 1865 अधिनियम, हिंदू विल अधिनियम, भारतीयों की परिवीक्षा पर अधिनियम और प्रशासन पर अधिनियम और यहां तक कि भारतीयों के उत्तराधिकार पर अधिनियम को समेकित करता है।

अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार कानून को संशोधित किया जाना है। यह काफी हद तक अंग्रेजी कानून के कोड को समाहित करता है। जहां तक उन चीजों का सवाल है जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में उनके व्यक्तिगत कानून द्वारा विनियमित किया जाता है। उनके व्यक्तिगत कानून की रक्षा के लिए, बहुसंख्यकों को भारतीयों द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिनमें हिंदू भी शामिल थे। बौद्ध, जैन या सिख, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा। ऐसे विशेष खंड अब भारतीय संपत्ति कानून में ही शामिल हैं। इसलिए वसीयत के हिंदू कानून को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयतनामा नियम के तहत खोजा और जांचा जाना चाहिए।

**मुख्यशब्द:** पारिवारिक कानून, भारतीय उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत, वसीयतनामा

**प्रस्तावना**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मुख्य रूप से निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित है न कि वसीयत से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की केवल धारा 30 ही हिंदुओं द्वारा पालन की जाने वाली वसीयत के संबंध में कानून की प्रक्रिया और प्रक्रिया प्रदान करती है। भारत के मुसलमान वसीयत के इस्लामी कानून, सुन्नी और शिया स्कूलों, या वसीयत से संबंधित स्थानीय रीति-रिवाजों द्वारा शासित होते हैं। भारत के मुसलमानों पर लागू वसीयत के इस्लामी कानून के नियम शास्त्रीय ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इस्लाम-पूर्व अरबों के रीति-रिवाजों और उपयोगों के बारे में प्राचीन काल के स्रोत बहुतायत से यह स्थापित करते प्रतीत होते हैं कि प्रायद्वीप की बुतपरस्त जनजातियों के बीच वसीयतनामा संबंधी स्वभाव अज्ञात नहीं थे। लेकिन उपलब्ध सामग्री से यह कहना मुश्किल है कि वे कौन सी स्थितियाँ थीं जो उनके द्वारा की गई वसीयत की वैधता या अमान्यता को नियंत्रित करती थीं। रैबिनिकल कानून, जो यहूदी जनजातियों के बीच लागू था, वसीयतकर्ता को उसके वैध उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित करने से रोकता था; इसने उसे किसी अजनबी को उत्तराधिकारी बनाने से भी रोक दिया। लेकिन जब कोई स्वभाव कब्जे की तत्काल डिलीवरी से प्रभावित होता था, तो रैबिनिकल कानून स्पष्ट रूप से इसे वैध मानता था। वसीयत या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में बनाई जा सकती है, लेकिन, सामान्य तौर पर, पहले तरीके को दोनों में से अधिक बेहतर माना जाता है।

कुरान ने स्पष्ट रूप से एक वसीयतनामा स्वभाव बनाने की शक्ति को मंजूरी दे दी है, और उन औपचारिकताओं और शर्तों को विनियमित किया है जिनके अधीन यह है। हेड्या कहते हैं, "वसीयतें," एक अनुकूल निर्माण पर वैध हैं। एनालॉग सुझाव देगा कि वे गैरकानूनी हैं, क्योंकि एक वसीयत एक तरह से किसी चीज़ के साथ एक बंदोबस्ती का प्रतीक है, जो इस तरह के बंदोबस्ती को उस समय संदर्भित करने का अवसर देती है जब संपत्ति मालिक (यानी वसीयतकर्ता) में शून्य हो गई है, और एक बंदोबस्ती के रूप में भविष्य की अवधि का संदर्भ (जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, 'कल मैं तुम्हें इस वस्तु का मालिक मानता हूं'), गैरकानूनी है, यह मानते हुए भी कि लेख में दाता की संपत्ति उस समय भी मौजूद है, इसका तात्पर्य यह है कि उस अवधि के लिए विलेख का निलंबन जब संपत्ति शून्य और शून्य है (जैसा कि पार्टी की मृत्यु पर), पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस्लामी कानून के तहत, एक वसीयतकर्ता वसीयतनामा के आधार पर अपने वैध उत्तराधिकारियों को विरासत में उनके हिस्से से वंचित नहीं कर सकता है और न ही अपनी संपत्ति के एक तिहाई से अधिक का निपटान कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में किसी उत्तराधिकारी के लिए वसीयत वैध नहीं है, भले ही वसीयत उसके पक्ष में हो। एक गैर-वारिस वसीयतकर्ता की संपत्ति के एक तिहाई की सीमा

तक वैध है, हालांकि वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी उस पर अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं।

भारत में इस कानून का कोई विधायी सुधार नहीं हुआ है और मुस्लिम वसीयत कानून के तहत किसी भी बड़े न्यायिक निर्णय में कट्टरपंथी सुधार का कोई तत्व शामिल नहीं है। ईसाई, पारसी, यहूदी, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, अपनी वसीयत के कानून को लगभग पूरी तरह से इस अधिनियम में पाते हैं, जबकि मुसलमान वसीयत के इस्लामी कानून द्वारा शासित होते हैं, लेकिन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के समान प्रक्रियात्मक नियमों का पालन किया जा सकता है। वसीयतकर्ता भारतीय आधुनिक कानून के तहत उत्तराधिकार, दोनों 'निर्वसीयत' और 'वसीयतनामा1 2 3 4 5', भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 19256 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम, केवल, समेकित करने वाला है, कोई संशोधन करने वाला नहीं7। इसने कई पूर्व अधिनियमों को समेकित और निरस्त कर दिया, और बदले में, बाद के कुछ अन्य अधिनियमों द्वारा संशोधित भी किया गया। अधिनियम में 392 धाराओं और नौ (ix) अनुसूचियों के साथ ग्यारह (xi) भाग शामिल हैं। वसीयतनामा उत्तराधिकार, जो इस शोध का विषय है, ज्यादातर अधिनियम के भाग छह (vi) द्वारा निपटाया गया है जिसमें 133 धारा (57-190) के साथ 23 अध्याय हैं। अधिनियम के भाग 8वें और 9वें में हमें कुछ धाराएँ मिलती हैं जो वसीयत के निष्पादन और प्रशासन से भी संबंधित हैं। इन दोनों भागों में क्रमशः छह खंड (211 से 216) और 151 खंड (218 से 369) शामिल हैं। यदि अधिनियम के अन्य भागों में, कुछ धाराएँ थीं, जो किसी तरह हमारे विषय से संबंधित थीं, यानी वसीयतनामा उत्तराधिकार, तो हमने उन पर भी ध्यान दिया है। यह अधिनियम उस दिन लागू हुआ जिस दिन इसे गवर्नर-जनरल की सहमति प्राप्त हुई, यानी 30 सितंबर 1925 को। यह माना गया कि अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था और यह 1890 (यानी पहले) में निष्पादित वसीयत पर लागू नहीं होता था। से 30.09.1925)9. इन पृष्ठों में इसे "आईएसए 1925" या केवल "आईएसए" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

इसी तरह, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 पूर्वव्यापी नहीं था और इसके लागू होने से पहले निष्पादित वसीयतों पर लागू नहीं होता था।10। मन में यह प्रश्न आ सकता है कि अधिकांश भारतीय या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं और हम जानते हैं कि उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में वे अपने निजी कानूनों द्वारा शासित होते हैं। फिर, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का क्या उपयोग है? उत्तर में, यह उल्लेख किया गया है कि जब अंग्रेज भारत पर शासन करने के लिए आये, तो उनके सामने लागू किये जाने वाले कानूनों की प्रकृति और घटनाओं का पता लगाने का कार्य आया। हालाँकि, देश में रहने वाले दो मुख्य समुदायों, अर्थात् हिंदू और मुसलमानों, के संदर्भ में इस मामले में कोई विशेष कठिनाई नहीं थी, क्योंकि, जैसा कि पहले कहा गया था, इनमें से प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून उसके पवित्र ग्रंथों में

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

सन्निहित थे, लेकिन जनसंख्या के अन्य छोटे वर्ग भी थे जो इनमें से किसी भी समुदाय से संबंधित नहीं थे और उन मामलों में किसी ऐसे धर्म के कानूनों को प्रशासित करना उचित नहीं था जिसके प्रति उनका कोई पालन या प्रतिबद्धता नहीं थी। ऐसे छोटे समुदायों में ईसाई, पारसी और यहूदी थे। तब, यह सोचा गया था कि मुख्य रूप से अंग्रेजी विश्व कानून पर आधारित उत्तराधिकार के कानून का अधिनियमन आवश्यकता को पूरा करता है और उपयुक्त संशोधनों और सुरक्षा उपायों के साथ इसे क़ानून 11 में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार, 1865 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ जो अंग्रेजी कानून12 पर आधारित था और कुछ अपवादों13 के अधीन ब्रिटिश भारत के कानून को निर्वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार के सभी वर्गों पर लागू घोषित किया गया था। हिंदू वसीयत अधिनियम, 1870 द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियमित किया गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का कुछ हिस्सा सितंबर 1870 के 1 दिन या उसके बाद किसी भी हिंदू द्वारा की गई सभी वसीयतों और संहिताओं पर लागू होना चाहिए। एक पारसी उत्तराधिकार अधिनियम पहले 1865 में अलग से अधिनियमित किया गया था।

प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, 1881, हिंदुओं और मुसलमानों पर भी लागू किया गया था। आई.एस.ए. 1925, अन्य बातों के साथ-साथ, 1865 के अधिनियम, हिंदू विल्स अधिनियम, प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम और पारसी इंटेस्टेट उत्तराधिकार अधिनियम को पुन: पेश करता है और काफी हद तक अंग्रेजी कानून के नियमों को शामिल करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (एचएसए) के लागू होने पर, हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकार धारा द्वारा अपवर्जित सीमा को छोड़कर इसके प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 5 उसमें14. इस धारा का खंड (i) उन हिंदुओं की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है जिनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954, (एसएमए)15 के तहत संपन्न हुआ है और ऐसे विवाह के मुद्दे की संपत्ति से संबंधित है। धारा के खंड (ii) और (iii) उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी गई अचल संपत्ति से संबंधित हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों की संपत्तियों का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा विनियमित होता है। उत्तराधिकार अधिनियम, मोटे तौर पर उत्तराधिकार को 'निर्वसीयत' और 'वसीयती उत्तराधिकार16' में विभाजित करता है। जबकि निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम के प्रावधान भारत में दो प्रमुख समुदायों, अर्थात् हिंदू और मुस्लिमों के वैयक्तिक कानून, वैधानिक और अन्यथा को छोड़ने वाले लोगों के विशेष वर्गों या समुदायों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधान वसीयतनामा से संबंधित हैं। उत्तराधिकार को आम तौर पर अधिनियम और कुछ अन्य के तहत छूट प्राप्त लोगों को छोड़कर भारत में सभी के लिए लागू किया जाता है।

धारा 30 कहती है:

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

"कोई भी हिंदू, वसीयत या अन्य वसीयतनामा द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान कर सकता है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या उस समय के किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा निपटाए जाने में सक्षम है। बलपूर्वक और हिंदुओं पर लागू।"

धारा के अंतर्गत स्पष्टीकरण. एच.एस.ए. का 30, उस धारा के कुछ अपवादों की गणना करता है। किसी भी अन्य क़ानून के विपरीत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में अधिनियम की सीमा के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम कुछ विषयों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों के आधार पर राज्यों (भारत के पूर्व प्रांतों) के अलावा सहायक कानून द्वारा कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। इस अधिनियम के प्रावधान 1963 के विनियम 6 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और 1980 के केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी अधिनियम 10 पर भी लागू होंगे। इस अधिनियम में शामिल कुछ भी पांडिचेरी 20 के केंद्र शासित प्रदेश के रेनो कैंट पर लागू नहीं होगा।

## भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 किस पर लागू होता है?

(1) जन्म या वंश से यूरोपीय लोग भारत में निवास करते थे। जहां तक अन्य यूरोपीय और अंग्रेजी प्रजा का संबंध है, यदि वे भारत में अचल संपत्ति रखते हुए मर जाते हैं, तो धारा के तहत। 521 ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकार भारत के कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा, अर्थात, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हुई है, तो उसके उत्तराधिकारियों का पता इस अधिनियम के भाग V में निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार लगाया जाएगा, और यदि उसने कोई वसीयत छोड़ी है, तो वसीयत भाग VI धारा के अध्याय III में निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए। 63-64, और ऐसी वसीयतों का प्रोबेट आवश्यक होगा।

(2) मिश्रित यूरोपीय और मूल रक्त के व्यक्ति और पूर्वी भारतीय।

(3) भारतीय ईसाई: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ईसाई वह व्यक्ति है जो ईसाई धर्म के किसी भी रूप को मानता है। अधिनियम की धारा 33 ए उन पर लागू नहीं होती है।

(4) यहूदी: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 पारित होने के बाद यह माना गया कि यहूदी उस अधिनियम द्वारा शासित थे और यहूदियों के व्यक्तिगत कानूनों को वसीयतनामा और निर्वसीयत क्षेत्राधिकार23 के संबंध में मान्यता नहीं दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद के एक मुकदमे में माना कि यहूदी कानून लागू था और राहत दी24। हालाँकि, इस निर्णय को बाद के मामले25 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेंजामिन वी.

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

बेंजामिन26 का अनुसरण करते हुए ऐसे ही मामलों27 में यहूदी कानून लागू किया।

(5) पारसी: वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम के भाग VI की सभी धाराएं पारसी पर लागू होती हैं।

(6) हिंदू: अधिनियम में "हिंदू" शब्द का उपयोग राष्ट्रीय या नस्लीय अर्थ से अलग एक धार्मिक अर्थ में किया गया है। इसमें पूर्ववर्ती कोचीन राज्य के आर्य समाजी28, ब्रह्मोस29 और मक्कथायी एझावा शामिल हैं जिनके लिए प्रथागत कानून; बेटियाँ पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार नहीं हैं, यह स्थापित किया गया था30। गैर-हिंदू मूल का व्यक्ति धर्मांतरण द्वारा हिंदू बन सकता है और हिंदुओं पर लागू इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे31। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30, अधिनियम के वसीयतनामा कानून (यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925) को भी हिंदुओं पर लागू करती है।

(7) जैन: यद्यपि जैन आम तौर पर हिंदू कानून द्वारा शासित होते हैं, फिर भी उन्हें अपनी विशिष्टताओं और रीति-रिवाजों द्वारा शासित होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। बहरहाल, हिंदू शब्द में जैन भी शामिल हैं34।

(8) सिख: यह माना गया कि हिंदू शब्द में सिख भी शामिल हैं35। लेकिन ईसाई धर्म अपनाने वाले सिख इस अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, न कि उस समुदाय के कानूनों और रीति-रिवाजों द्वारा, जिससे वे संबंधित हैं36।

(9) बौद्ध: यह माना जाता था कि बर्मी, जिन्हें कालिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बर्मी महिलाओं से शादी की थी, वे इस अधिनियम 37 द्वारा शासित थे। लेकिन एक चाइनामैन जो बौद्ध है, कार्यकाल के अंतर्गत आता है और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार और उत्तराधिकार बर्मा के बौद्ध कानून द्वारा शासित होता है38। लेकिन चीनी बौद्ध (बर्मा में अधिवासी) इस अधिनियम द्वारा शासित बर्मा को भारत से अलग करने से पहले थे।

सिक्किम में बौद्ध के लिए वसीयतनामा स्वभाव को अधिकृत करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है। लेकिन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में वसीयत के निष्पादन, व्याख्या या प्रभाव से संबंधित प्रावधान, जिसमें प्रोबेट और प्रशासन पत्र के अनुदान और अपील और अन्य कार्यवाही से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, सिक्किम बौद्धों पर लागू होंगे, क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 सिक्किम का कानून बन गया40। अनुभाग; 60, 65, 66, 69, 72, 91 से 94, 97,100,118 और 191 धारा के प्रावधानों के अधीन, किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा की गई वसीयत और कोडिसिल पर लागू नहीं होते हैं। अधिनियम 41 का 57. इसके अलावा, सेक. अधिनियम की धारा 118, केवल बम्बई राज्य में उन पर लागू नहीं होती है।

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

**भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 किस पर लागू नहीं होता**

(1) क्राउन: भारत के गणतंत्र बनने से पहले यह अधिनियम क्राउन पर लागू नहीं होता था42। यहां तक कि जब संपत्ति क्राउन (अब राष्ट्रपति) में निहित होती है, तब भी अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन मृतक के लेनदार, जिनकी संपत्ति क्राउन के पास चली जाती है, को धारा 21843 के तहत प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन करने का अधिकार है।

(2) अर्मेनियाई: अर्मेनियाई लोगों को अंग्रेजी कानून44 द्वारा शासित माना जाता था।

(3) पुर्तगाली: वे अंग्रेजी कानून45 द्वारा शासित होते हैं। मा लेट बनाम माउंग चित, 48 टी.ए. 553; 49 कैल. 310 टैन मा श्वे बनाम केडो सू चोंग, (1939) रंग। 548 मैन सैन बनाम मा चित, ए.आई.आर. (1930) आर. 219; फान तियोक बनाम लिर। किम, 8 रैंड 57 (एफ.बी.) सोनम टोपग्याल बनाम गोम्पू, ए. 1980 सिक्किम 33. अनुभाग सचिव राज्य बनाम गिरदाबरीलाल, 54 ए11.226 के पाठ देखें। Akileswarv. बंगाल राज्य, 59 सी.डब्ल्यू.एन. 240. निकोलस बनाम एस्पर, 24 कैल। 216 10

(4) ब्रह्मोस: एक ब्रह्मो अधिनियम, 1865 द्वारा शासित नहीं था, बल्कि प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 द्वारा शासित था, क्योंकि एक ब्रह्मो केवल ब्रह्मो46 बन जाने से हिंदू नहीं रह जाता था।

(5) रेनोकैंट्स: इस अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी47 के रेनोनैंट्स पर लागू नहीं होंगे। जहां तक अधिनियम के भागों का संबंध है, भाग VI के अलावा अन्य धाराएं: 4 से 19 (अधिवास), 20 से 22 (विवाह), 23 से 28 (विवाह), 29 से 49 (निर्वसीयत उत्तराधिकार), भी लागू नहीं होती हैं। किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन को। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा के तहत किसी भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन है, के निर्वसीयत उत्तराधिकार पर लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के 2। ऊपर उल्लिखित बाद की धाराएं, और धाराएं। 57 से 191 (अर्थात् वसीयती उत्तराधिकार) मुसलमानों पर लागू नहीं होते। यानी बाकी धाराएं मुसलमानों पर भी लागू होती हैं. लेकिन, जैसा कि पहले याद दिलाया गया है, वे व्यक्ति जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह किया है, उनकी संपत्तियों का उत्तराधिकार और ऐसे विवाह के मुद्दों की संपत्तियों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाएगा, हालांकि वे व्यक्ति कुछ समुदायों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू आदि, जिनके पास अपनी संपत्तियों के उत्तराधिकार को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानून हैं। एस.एम.ए. की धारा 21। ने मामले को स्पष्ट कर दिया48. हम जानते हैं कि भारत में, कुछ कारणों से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन बहुत प्रचलित था, इसलिए एक और सवाल जो उठ सकता है वह यह है

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

कि धर्म परिवर्तन के उत्तराधिकार के मामले में कौन से कानून और नियम लागू होने चाहिए?

1865 के उत्तराधिकार अधिनियम x के पारित होने से पहले धर्मांतरितों पर लागू होने वाला कानून व्यवस्थित स्थिति में नहीं था। इब्राहीम बनाम अब्राहम50 में प्रिवी काउंसिल49 के समक्ष यह प्रश्न आया और उनके आधिपत्य ने इस प्रकार राय दी: "कि एक हिंदू के ईसाई धर्म में रूपांतरण पर, हिंदू कानून का धर्मांतरित व्यक्ति पर कोई निरंतर अनिवार्य बल समाप्त हो जाता है। वह पुराने धर्म का त्याग कर सकता है। ईसाई धर्म का पेशा धर्मांतरित व्यक्ति को हिंदू कानून के बंधनों से मुक्त करता है, लेकिन इसमें आवश्यक रूप से उन मामलों में धर्मांतरित व्यक्ति के अधिकारों या संबंधों में कोई बदलाव शामिल नहीं है, जिनसे ईसाई धर्म का कोई सरोकार नहीं है, जैसे कि उसके अधिकार और हित , और संपत्ति पर उसकी शक्ति। इस प्रकार, मूल ईसाई और ऐसी अन्य मूल जनजातियाँ, जो हिंदू या मुस्लिम कानून द्वारा शासित नहीं हैं, उस कानून द्वारा शासित होंगे जिसे उन्होंने अपने आचरण के दौरान अपनाया है या प्रथागत कानून द्वारा जिसका उन्होंने पालन किया है। अनादिकाल51. लेकिन अधिनियम 1865 के लागू होने के बाद से अब्राहम के मामले में निर्णय ने अपना प्रभाव खो दिया है और बाद के अन्य मामलों52 में, यह माना गया कि यह अधिनियम और इसके द्वारा निर्धारित विरासत के नियम उन हिंदुओं पर लागू होते हैं जो ईसाई बन जाते हैं और यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि वे और जिस समुदाय से वे संबंधित थे, उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों को बरकरार रखा, जो अस्वीकार्य था। अब्राहम और श्री गजपति के मामलों के निर्णय को 1865 के उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने से पहले के निर्णय के रूप में माना गया और माना गया कि यदि ईसाई धर्म में परिवर्तित एक हिंदू की ईसाई के रूप में मृत्यु हो जाती है तो वह उस अधिनियम द्वारा शासित होता है।

उसे यह चुनने का अधिकार नहीं है कि वह विरासत के हिंदू कानून द्वारा शासित है53। अगले चरण में, हम तीन व्यक्तियों के अधिकारों पर धर्म परिवर्तन के प्रभाव को समझाने का प्रयास करेंगे (1) संयुक्त परिवार की संपत्ति में धर्म परिवर्तन करने वाले के अधिकार, (2) धर्म परिवर्तन करने वाले की संपत्ति में हिंदू संबंध के अधिकार, और (3) ) अपने हिंदू रिश्तेदारों की संपत्ति पर एक परिवर्तित रिश्ते के अधिकार। हिंदू कानून के अनुसार प्रत्येक सहदायिक का जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में निहित स्वार्थ होता है। यह अधिनियम (यानी आई.एस.ए. 1865) उन लोगों के बीच सहदायिक जहाज के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है जिन पर यह लागू होता है। यह अधिनियम सहदायिक 54 का कोई निहित अधिकार नहीं छीनता है। यह भी माना गया कि सहदायिक के जीवित रहने का अधिकार आकस्मिक अधिकार था। इसलिए, यदि ए और बी, सहदायिक भाई होने के नाते संयुक्त रूप से संपत्ति के मालिक हैं और यदि ए ईसाई बन जाता है और यदि उत्तराधिकार अधिनियम पारित होने के बाद बी की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तरजीविता द्वारा पूरी

संपत्ति पर कब्जा करने का ए का अधिकार खत्म हो जाता है55। हालाँकि, इस निर्णय को बाद के मामले56 में अस्वीकार कर दिया गया है जहाँ यह माना गया था कि उत्तराधिकार अधिनियम सहदायिक जहाज के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

एक अन्य मामले में यह माना गया कि संयुक्त हिंदू परिवार के एक सदस्य के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर, सदस्य पैतृक संपत्ति को संयुक्त मालिक के रूप में रखता रहा और वह इस आधार पर अपने हिस्से का कब्ज़ा वापस पाने का हकदार था कि उसका विघटन हुआ था। उसके रूपांतरण की तिथि पर परिवार, कि वह अपने पिता के ऋणों और अपने रूपांतरण की तिथि के बाद पैतृक संपत्ति पर लगाए गए शुल्क को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लेकिन रूपांतरण से पहले किए गए ऋणों के लिए उत्तरदायी था। एक मामले में जब एक हिंदू मुस्लिम बन गया और उसने एक मुस्लिम पत्नी से शादी की, पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ, और बेटे के हिंदू चाचा की संपत्ति छोड़कर मृत्यु हो गई, तो बेटे ने संपत्ति को अपने चाचा के उत्तराधिकारी के रूप में दावा करते हुए मुकदमा दायर किया और उसका दावा था अनुमत। लेकिन मितर सेन के मामले में प्रिवी काउंसिल ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया। जब कोई ईसाई मुस्लिम बन जाता था, तो यह माना जाता था कि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार मुस्लिम कानून द्वारा नियंत्रित होता था, न कि इस अधिनियम द्वारा।

**निष्कर्ष**

1865 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पहले भारत में नियंत्रित था। यह अधिनियम मुख्य रूप से अंग्रेजी कानूनों पर आधारित था और कुछ अपवादों के अधीन, सभी प्रकार की वसीयत और वसीयती उत्तराधिकार के लिए प्रभावी नियम था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में यह प्रावधान है कि कोई भी हिंदू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी संपत्ति का निपटान वसीयत या अन्य वसीयतनामा द्वारा कर सकता है, जो उसके द्वारा निपटाए जाने में सक्षम है। लागू. ये प्रावधान वसीयत बनाने की कानूनी क्षमता से संबंधित हैं और कौन वसीयत बना सकता है और कौन नहीं बना सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 59 का स्पष्टीकरण (1) स्पष्ट करता है कि एक विवाहित महिला द्वारा वसीयत द्वारा किस चीज़ का निपटान किया जा सकता है और कहा गया है कि कोई भी संपत्ति जिसे वह अपने जीवन के दौरान अपने स्वयं के कार्य द्वारा अलग कर सकती है, उसे वसीयत द्वारा निपटाया जा सकता है। यह इस प्रकार है कि विवाहित महिला जो अपने जीवन के दौरान अपने कृत्य से किसी संपत्ति को अलग नहीं कर सकती है, वह वसीयत द्वारा संपत्ति का निपटान नहीं कर सकती है। 18 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 सहदायिक द्वारा सहदायिक में अपने अविभाजित हित के उपहार पर रोक नहीं लगाती है। किसी अन्य सहदायिक को या

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

यहां तक कि किसी अजनबी को भी। हिंदू कानून के तहत, एकमात्र जीवित सहदायिक अपनी संयुक्त परिवार की संपत्ति की वसीयत कर सकता है जैसे कि वह उसकी अलग संपत्ति हो। किसी सहदायिक द्वारा निष्पादित वसीयत को केवल सहदायिक के किसी अन्य सदस्य द्वारा चुनौती दी जा सकती है। सहदायिक संपत्ति को जीवित सहदायिक द्वारा वसीयत की जा सकती है। पुराने हिंदू कानून के तहत संपत्ति में अपने अविभाजित हित को वसीयत या अन्य कानूनी दस्तावेज के जरिए निपटाने में सहदायिक की अक्षमता को अधिनियम की धारा द्वारा हटा दिया गया है। पूर्वजों से विरासत में मिली संपत्तियों से प्राप्त आय को संयुक्त परिवार की संपत्तियों के रूप में माना जाएगा, न कि स्व-अर्जित संपत्तियों के रूप में। यह साबित करने का भार कि ऐसी संपत्तियाँ स्व-अर्जित संपत्ति हैं, ऐसा दावा या दावा करने वाले सहदायिक पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयत के तहत संपत्तियों का विभाजन पारिवारिक संपत्तियों को उनके बच्चों के बीच बांट रहा है और संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्तियां हैं, अन्य सहदायिकों की सहमति के बिना वसीयत के तहत उक्त संपत्तियों को वसीयत करना उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए, वसीयत उन पर बाध्यकारी नहीं है। केवल यह तथ्य कि वसीयत में कुछ प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया गया था, वसीयत को अमान्य नहीं कर देगा। एक वैध रूप से निष्पादित वसीयत, जो अदालत के समक्ष उचित साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो, को केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

बॉटमली, ऐनी (एड), फ़ाउंडेशनल सब्जेक्ट एंड लॉ पर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, कैवेंडिश पब्लिशिंग लिमिटेड, ब्रिटेन 1992।

चक्रवर्ती, कृष्णा, फैमिली इन इंडिया, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002।

चंपापिल्ली, सेबेस्टियन (एड), क्रिश्चियन लॉ ऑफ डिवोर्स, सदर्न लॉ पब्लिशर्स कोचीन, 2007।

चंद्रा, सुधीर, गुलाम बेटियाँ: उपनिवेशवाद, कानून और महिला अधिकार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुंबई, 1998।

चावला, मोनिका, जेंडर जस्टिस: वीमेन एंड लॉ इन इंडिया, डीप एंड डीप पब्लिकेशन प्राइवेट, नई दिल्ली, 2006।

कोहरेन, माइकल. जी., क्या हमें सहवास समझौते की आवश्यकता है, जॉन विली एंड संस कनाडा लिमिटेड, कनाडा, 2010।

क्रेनी, एस. एम. और जे. एम. मैसन, पारिवारिक कानून के सिद्धांत, 5वां संस्करण, स्वीट और मैक्सवेल, लंदन, 1990

क्रेटनी, स्टीफ़सन। एम, पारिवारिक कानून के सिद्धांत, चौथा संस्करण, स्वीट एंड मैक्सवेल, लंदन, 1984।

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

डेल होर्बर्ग, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (इंडिया लिमिटेड)।

दास पी.के., घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2011।

डेरेट, जे. डंकन। एम. विवाह कानून की मृत्यु: ऋषियों के लिए समाधि-लेख, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड, दिल्ली, 1978।

देसाई कुमुद, भारतीय विवाह और तलाक कानून, चौथा संस्करण, एन.एम. त्रिपाठी प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे, 1981।

देसाई, सत्यजीत. ए., मुल्ला, हिंदू कानून के सिद्धांत, 17वां संस्करण, बटरवर्थ्स, नई दिल्ली, 1998।

ढांडा, अमिता, अर्चना पाराशर, एन्जेंडरिंग लॉ, लोटिका सरकार के सम्मान में निबंध, ईस्टर्न बुक्स कंपनी, लखनऊ, 1999।

दीवान, पारस और पियाशी दीवान, पारिवारिक कानून: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, दूसरा संस्करण, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 1994।

दीवान, पारस और पीयूषी दीवान, विवाह और तलाक का कानून, दूसरा संस्करण, वाधवा एंड कंपनी, इलाहाबाद, 1991।

दीवान, पारस और पीयूषी दीवान, दहेज और विवाहित महिला की सुरक्षा, तीसरा संस्करण, दीप और दीप प्रकाशन नई दिल्ली, 1995।